



दैनिक

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, रामपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।

दैनिक बुद्ध का संदेश

8795951917, 9415163471

@budhakasandesh

budhakasandeshnews@gmail.com

www.budhakasandesh.com

उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

एक विश्वास....

स्कैल्प सीरम का इस्तेमाल करने ...8

सिद्धार्थनगर

शनिवार , 04 जलाई 2026

वर्ष: 13 अंक : 202 पृष्ठ: 8

आमंत्रण मूल्य 2/-रुपया

सम्पादक : राजेश शर्मा

पहचान के संकट से निकलकर रूपी बना देश

की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्था: सीएम योगी का दावा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि पिछले नौ सालों में राज्य ने बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर भारत की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने का सफर तय किया है। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय अच्छे शासन, टीम वर्क और टेक्नोलॉजी के प्रभावी इस्तेमाल को दिया। डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के नए अत्याधुनिक परिसर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि

पिछले नौ वर्षों में राज्य की विकास यात्रा शासन और लोगों की सोच में आए बदलाव को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ सालों में, उत्तर प्रदेश उस पहचान के संकट से बाहर निकल आया है जिसका सामना उसे कभी करना पड़ा था। आज राज्य ने खुद को उन राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर लिया है, जहाँ न तो सरकार, न ही प्रशासनिक तंत्र और न ही जनता को पहचान के संकट का सामना करना पड़ता है। राज्य की आर्थिक प्रगति का



जिक्र करते हुए बड योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे पिछड़ी पाँच अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इसने श्वीमारू राज्य के तप्पे से मुक्ति पाई है, सुरक्षा और

सुशासन के नए मानक स्थापित किए हैं, भीड़-भाड़ के प्रभावी प्रबंधन का उदाहरण पेश किया है और यह दिखाया है कि तकनीक किस तरह आम नागरिकों के जीवन को बदल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन का स्वरूप न केवल राजनीतिक नेतृत्व से, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के कामकाज से भी तय होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के बारे में जनता की राय प्रशासनिक तंत्र के कामकाज से बनती है। नौकरशाही सरकार और जनता

के बीच एक पुल का काम करती है। जब यह पुल प्रभावी ढंग से काम करता है, तो सरकारी योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचती हैं और लोगों की सोच बदलती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधारों का जिक्र करते हुए, सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले राशन वितरण को लेकर शिकायतें आम थीं, लेकिन म-चै मशीनें आने के बाद इनमें काफी कमी आई। उन्होंने कहा कि हमने म-चै मशीनें लगाई और शिकायतें बंद हो गईं। टेक्नोलॉजी ने आम आदमी की समस्या का समाधान किया।

राम भक्तों की श्रद्धा को आघात...

संघ ने जारी किया बयान, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली। अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन पर प्रतिक्रिया देते हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हिंदू समुदाय से इस मुश्किल समय में धैर्य और संयम बरतने की अपील की। होसाबले ने कहा, अयोध्या में श्री राम लल्ला मंदिर में रखे दान-पात्रों से चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे समाज और राम भक्तों की भावनाओं और श्रद्धा को आहत किया है, और हम सभी इस घटना से दुखी हैं। राम मंदिर में दान में कथित हेराफेरी का मामला 7 जून को सामने

आया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT की शुरुआती रिपोर्ट उन्होंने कहा, प्यह पक्का करना जरूरी है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसे कड़ी सजा मिले। RSS का रुख बताते हुए श्री होसबोले ने कहा, छ्दस बेहद निंदनीय घटना को एक अपवाद के तौर पर देखा जाना चाहिए और इंतजामों व कामकाज में मौजूद सभी कमियों को दूर करने के लिए पूरी गंभीरता से असरदार कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि अयोध्या मंदिर में जा चुका है और जांच जारी है। करोड़ों राम भक्तों का भरोसा और श्रद्धा अटूट और अडिग बनी रहे।



राम मंदिर चंदे पर संग्राम: बीजेपी

बोली एसआईटी पर भरोसा रखें

विपक्ष का पलटवार-असली चेहरा बेनकाब

अयोध्या। राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी के मामले ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष ने सत्ताधारी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, जबकि सरकार का कहना है कि मामले की पारदर्शी जांच चल रही है। इस मामले पर 18 से बात करते हुए बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 'पूज' जांच के आदेश दिए हैं। 'पूज' जांच चल रही है और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जा रही है। लोगों को इंतजार करना



होता था, लेकिन सब कुछ दबा दिया जाता था। खरप लोगो को, संरक्षण मिलता था। हालांकि, हमारे कार्यकाल में ऐसे मामलों का खुलासा हो रहा है और दोषियों को सजा दी जा रही है। जांच पर भरोसा रखना चाहिए। आरोपियों को बचाने और जनता को गुमराह करने वाले बयान देने के बजाय, भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा जब तक फाइल बंद नहीं हो जाती, जांच एक खास प्रक्रिया के तहत चलती है। बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता।

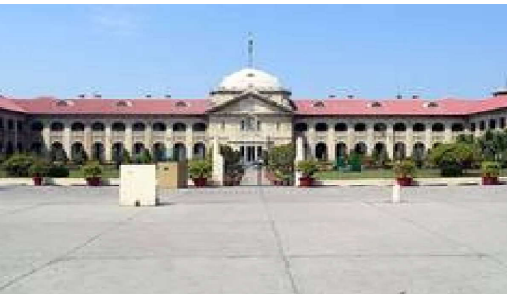
राज्य के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 18 से कहा कि पिछली सरकारों के उलट, मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार को छिपा नहीं रही है। निषाद ने ANI से कहा भ्रष्टाचार पहले भी

निकाह हलाला की आड़ में नाबालिग से गैंग रेप ? हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि निकाह हलाला और तीन तलाक जैसी प्रथाओं की आड़ में महिलाओं का यौन शोषण नहीं होने दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ (निजी कानूनों) की आड़ में अपराधों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब वे एक महिला के पूर्व पति, एक मौलवी, रिश्तेदारों और अन्य आरोपियों की उन याचिकाओं को खारिज कर रहे थे जिनमें उनके खिलाफ दर्ज थक को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह मामला उत्तर प्रदेश के अमरौहा जिले का है, जहां एक

महिला ने कम उम्र में शादी, तीन तलाक, निकाह हलाला और दोबारा शादी की आड़ में बार-बार यौन शोषण का आरोप लगाया था। निकाह हलाला के तहत, तलाकशुदा महिला को अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने से पहले किसी दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है और फिर उससे अलग होना पड़ता है। ट्रिपल तलाक, जिसे शतलाक-ए-बिदतश भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रथा है जिसमें मुस्लिम पुरुष एक ही बार में तीन बार फ्तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। भारत में 2019 में इस प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया था।

आरोपी की दलीलों को



खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपों से बहुत गंभीर प्रकृति के तथ्य सामने आए हैं और प्रथम दृष्टया ये कानून के खिलाफ लगते हैं। बेंच ने कहा कि इस मामले में अपनाई गई कथित प्रथाएं समाज के लिए एक फ्काला अध्याय हैं और ये संवैधानिक मूल्यों, समानता और

मानवीय गरिमा के खिलाफ हैं। अदालत ने कहा कि ये हरकतें न सिर्फ कानून की आड़ में किए गए अपराध हैं, बल्कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को भी झकझोर देती हैं। साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि आपराधिक गतिविधियों को बचाने के लिए पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत

कानूनों) का इस्तेमाल ढाल के तौर पर नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें शनिकाह हलाला और उससे जुड़ी प्रथाओं के कथित गलत इस्तेमाल के जरिए एक महिला के यौन शोषण के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ दर्ज थक को रद्द करने की मांग की गई थी। आरोपियों ने केंस की सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी से सुरक्षा की भी मांग की थी। हालांकि, कोर्ट को इस चरण पर जांच में दखल देने का कोई आधार नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया एक नाबालिग के साथ सुनियोजित गैंगरेप का मामला लगता है और इसकी गहन जांच

जरूरी है। FIR के मुताबिक, शिकायत करने वाली महिला को अप्रैल 2015 में, जब वह लगभग 15 साल की थी, कथित तौर पर अजहर नवाज से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। जनवरी 2016 में अजहर द्वारा कथित तौर पर तीन तलाक देने के बाद, उसे 2017 में अजहर से दोबारा शादी करने से पहले मौलाना कध्द्यू के साथ निकाह हलाला करने के लिए मजबूर किया गया। श्लॉबीटर (सूतमंज) की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने गौर किया कि पहले हलाला के समय वह नाबालिग रही होगी। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2021 में एक और तलाक के बाद, अजहर ने सुलह की कोशिश की।

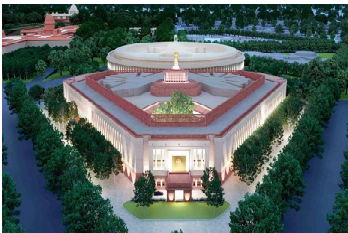


मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाबा बर्फानी की यह यात्रा हमारी परंपराओं को जोड़ती है। उन्होंने दुआ की कि सभी शिव भक्तों की यह यात्रा सुरक्षित और बहुत अच्छी रहे। सोशल मीडिया पर शेयर किया पत्र: पीएम मोदी ने पोस्ट के साथ एक लेटर की तस्वीरें भी शेयर कीं। इस लेटर में उन्होंने यात्रियों के लिए 5 जरूरी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक भारत, श्रेष्ठ भारत की मिसाल है, जहां पूरे देश से अलग-अलग भाषाओं और राज्यों के लोग भगवान शिव की भक्ति में एक साथ आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर के लोगों की भी तारीफ की जो हर साल दिल खोलकर यात्रियों का स्वागत करते हैं। यात्रा को सफल बनाने वालों का शुक्रिया: प्रधानमंत्री ने सेना, पुलिस, डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों और लोकल प्रशासन का दिल से धन्यवाद किया, जो दिन-रात काम करके इस यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाते हैं।

संसद में होगी आर-पार की लड़ाई

कई अहम बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार!

नई दिल्ली। संसद के मौनसून सत्र में जबरदस्त राजनीतिक टकराव की उम्मीद है, जो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, चार हफ्ते के इस सत्र में 19 बैठकें हो सकती हैं। कई क्षेत्रीय पार्टियों में हो रहे राजनीतिक बदलावों और सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे आक्रामक विपक्ष के कारण, इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने की



पहले, लोकसभा स्पीकर बागी तुणमूल कांग्रेस (जड्ड) के 20 सांसदों और शिवसेना के छह सांसदों के शिवसेना (शिंदे गुट)

में विलय के मामले पर फैसला ले सकते हैं। लोकसभा में इन बागी सांसदों के बैठने की व्यवस्था पर भी फैसला होने की संभावना है। एनडीए सरकार, जो दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के करीब है, इस सत्र के दौरान कई अहम कानून पास कराने की तैयारी कर रही है, जिनमें संविधान संशोधन के दो बिल भी शामिल हैं। सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन

से जुड़े 131वें संविधान संशोधन बिल को प्रस्तावित संशोधनों के साथ फिर से पेश कर सकती है। इस संशोधित बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 50: तक बढ़ाने का प्रावधान शामिल हो सकता है। 130वें संविधान संशोधन बिल में यह प्रस्ताव हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री 30 दिन से ज्यादा समय तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा।

सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के अधीन काम कर रहा है

राम मंदिर मुद्दे पर संजय राउत का बड़ा बयान

मुंबई। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के चंदे में हुई कथित धोखाधड़ी का मामला इन दिनों काफी गरमाया हुआ है। इस पूरे प्रकरण की तपतीश में जुटी एसआईटी अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच, पूरे विवाद पर शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आड़े हाथों लिया है। संजय राउत ने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी की नहीं पूरी देश की भावना है। अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूंगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज हैं माथे जामदार उनके निगरानी में जांच होनी



चाहिए। अब बहुत कम लोग बच्चे इस देश के न्याय व्यवस्था में। राउत ने कहा कि हां जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा राम की अयोध्या रही उसका अब अंडरवर बन गया है जो मुंबई में अंडरवर है ना गुंडुम का और अंडरवर चलाने वाले बीजेपी के लोग सबसे पहले

डाका डाला है राम मंदिर पे अब कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें वह बम डालने को आएगा उसके पास आरडीएक्स है टैरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? यह बीजेपी के महमूद गजनवी ने अंडरव चला रहे लोग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि बुजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता है जो कभी किसी को डरते नहीं वो नेताजी ने भी कहा कि मुझे डर लगता है नाम लेने। वो जो अपने आप को भगवान मानने वाले भागेश्वर बाबा बोलते हैं मुझे भी डर लगता है। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि मेरी हत्या हो जाएगी अगर मैंने नाम लिया तो ये किसका डर है? ये कौन सा अंडरवर अयोध्या में काम कर रहा है? बताइए।

जाए। निरीक्षण के दौरान एडीओ कृषि, बडौपुर द्वारा खाद दुकानों का निरीक्षण न किए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नोटिस जारी करने तथा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि अधिकारी रविशंकर पाण्डेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

सम्पादकीय

जिसे अविलंब दूर करने की भी जरूरत है। इस वैकल्पिक ईंधन की सहज उपलब्धता के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व गाड़ियों को इसके अनुरूप बनाना, वैकल्पिक ईंधन की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण तथा इससे जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बाॅयोफ्यूल इतनी जल्दी फक्षसिल फ्यूल का विकल्प नहीं बन सकता। इस बाबत पर्याप्त तैयारी...

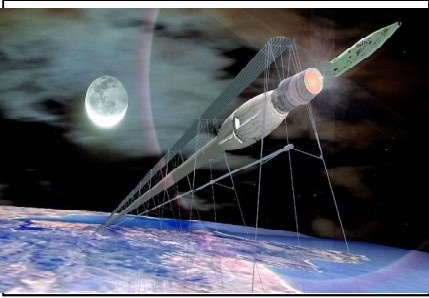
सरकार की आंख के तारे, करें हरदम वारे-न्यारे

सरकार को सरकारने की सारी जिम्मेदारी जिसकी होती है, उसे सरकारी कर्मचारी कहते हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकार को हवा का पर्यायवाची मानता है, इसलिए जिस तरफ हवा चलती है, उसी तरफ पीठ कर लेता है। सरकार को सरकारने की सारी जिम्मेदारी जिसकी होती है, उसे सरकारी कर्मचारी कहते हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकार को हवा का पर्यायवाची मानता है, इसलिए जिस तरफ हवा चलती है, उसी तरफ पीठ कर लेता है। वायु, वाम-दक्षिण, ऊर्ध्व-अधो... किधर भी चले, वह उसी दिशा में सांस लेता है। कर्मचारी की एक विशेषता यह होती है कि वह सरकार से डरता है। सरकार के विरुद्ध कुछ सुनकर कान बंद कर लेता है। अखबार नहीं पढ़ता क्योंकि उनमें सरकार के खिलाफ भी छपता है। टीवी में वह न्यूज चैनलों को ब्लॉक करके रखता है कि कहीं सरकार देख न ले कि वह सरकार के विरुद्ध समाचारों देख रहा है। वह सरकार का दिया खाता है, इसलिए ईमानदारी से उसे भी निभाता है। वह व्हाट्सएप समूह में भी जुड़ा है। नियम से गुड मॉर्निंग के फूल-पत्ती वाले संदेश डालता है। कभी-कभी वह मंत्री जी को माला पहनाते हुए अपनी तस्वीर डालता है। कोई सरकार के खिलाफ संदेश भेजता है तो एडमिन होने के नाते वह उसे डिलीट कर देता है। डिलीट करने से पहले वह बताता, ‘यह सरकारी समूह है, इसमें सरकार के खिलाफ लिखना अशोभनीय है। दंडनीय है। अवांछित है... वर्जनीय है... और नहीं क्क्या-क्क्या है।’ जब कभी उसके अन्य साथी, तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, वह आंदोलन में सबसे पीछे चेहरा ढांपकर खड़ा होता है। सरकार के खिलाफ नारे वह मन में भी नहीं लगाता। कहता है, ‘सरकार के खिलाफ सारे आंदोलन, इतवार को होने चाहिए।’ वह काली पट्टी भी कमीज के भीतर बांधता है। उसका मानना है कि ‘जब सब कि तनख्वाह बढ़ेगी तो उसकी भी बढ़ेगी। फिर क्क्यों सरकार के खिलाफ जाना?’ ऐसे कर्मचारी को सरकार बुलाती, ‘अमुक कुमार! अब मैं तेरा ट्रान्सफर नहीं करूंगी। तू आराम से बिना काम किए तनख्वाह उठा। अपना निजी धंधे करते हुए सरकारी नौकरी भी कर। अब तू अपना एक नया सच बना ले... और मैं जैसा कहूँ वैसा मेरा विरोध ा कर।’ उसने तत्काल एक संगठन बनाया, ‘सरकार का प्रबलतम विरोधी संगठन’। उसका वह आजीवन अध्यक्ष बन गया। सरकार ने तत्काल उसे मान्यता दी। वह सरकार से लड़ने के नाम पर अपने साथियों से चंदा लेने लगा। आज वह, मंत्री का दर्जा प्राप्त सरकारी कर्मचारी नेता है। सरकार ने जैसा उसे दिया वैसा सब को दे।

मगर सवाल है, क्या हमारी सीमाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संचालित रॉकेट प्रणाली से सुरक्षित रहेंगी ? चीन के साथ भारत की 4,056 किलोमीटर लंबी सीमा को दशकों से नजरअंदाज किया गया है। समय-समय पर भारतीय अधिकारी इसे अभेद बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। सत्ता में आने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पिछली सरकार के ...

चीन का मानना ​​​​है कि 'दुनिया की छत' (मैग्नेटिक फील्ड) का उपयोग तिब्बत से लॉन्च किए गए रॉकेट भारत के भीतर तक जा सकते हैं। चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लॉन्च किया गया रॉकेट पारम्परिक रॉकेट से अधिक स्थिर और अचूक होगा, साथ ही यह अपने भार को गति देने वाली मिसाइल से बहुत सस्ता भी होगा। जो तिब्बत 'दुनिया की छत' के नाम से मशहूर था, अब चीन उसे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मार्ग वाले रॉकेट लॉन्चिंग अधिकेंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। पेइचिंग इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस के अंतरिक्ष विज्ञानी यू थांग ने पिछले हफ्ते कहा, 'चीन की स्पेस इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही साहसी और होनहार युवाओं ने दो दशक से भी ज्यादा समय पहले शिंगहाई-तिब्बत पठार के ऊंचाई वाले और कम हवा वाले इलाकों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च ऑर्बिट बनाने का आइडिया दिया था। अब वो साकार हो रहा है।' इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी, एक क्रांतिकारी अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली है, जो पारंपरिक केमिकल, ईंधन के बजाय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों

(मैग्नेटिक फील्ड) का उपयोग करके रॉकेट या पेलोड को अंतरिक्ष में लॉन्च करती है। यह तकनीक लक्ष्य तक पहुंचने में सटीक है, और अंतरिक्ष यात्रा की लागत को काफी हद तक कम करने की क्षमता रखती है। इस प्रणाली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैक (विद्युत चुम्बकीय पटरियों) का उपयोग किया जाता है, जो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा (कायनेटिक एनर्जी) में बदलती हैं। एक बार आवश्यक गति प्राप्त करने के बाद, पेलोड या छोटा रॉकेट वातावरण में ऊपर की ओर छूट जाता है, और अंतरिक्ष के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है। इससे भारी मात्रा में ईंधन की बचत होती है। इसे ध्यान में रखें कि पारंपरिक रॉकेटों के कुल वजन का 80–90 प्रतिशत हिस्सा केवल ईंधन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर इस ईंधन के भार को खत्म कर देते हैं, जिससे रॉकेट बहुत अधिक पेलोड (उपग्रह या उपकरण) ले जा सकते हैं। यह तकनीक



अंतरिक्ष यान को पारंपरिक केमिकल इंजनों की तुलना में कहीं अधिक गति देती है। इससे मंगल ग्रह की यात्रा का समय 8–9 महीने से घटकर केवल 30–60 दिन होने का दावा किया जा रहा है। यह 300 किलोवाट तक की शक्ति पर काम करता है, और हाइड्रोजन के आवेशित कणों (प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन) को 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की आश्चर्यजनक गति प्रदान करता है। भारत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक (विद्युत-चुंबकीय) रॉकेट लॉन्च तकनीक अभी भी शुरुआती अनुसंधान और विकास के चरण में है।

पहले हितधारकों की चिंताओं को दूर कीजिए

खाड़ी युद्ध के चलते उपजे ईंधन संकट ने भारत समेत पूरी दुनिया को सबक दिए हैं कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये नये विकल्प तलाशे जाएं। भारत जैसे देश के लिये तो यह बड़ी चुनौती है क्योंकि हम पूरी तरह कच्चे तेल व गैस के लिये विदेशी संसाधनों पर ही निर्भर हैं। जिससे संकटपूर्ण स्थितियों में न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि हमारी दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी दांव पर लगती है। ऐसे ही संकट से जूझने के लिये देश ने इथेनॉल के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया। देश में पहले ही सामान्य पेट्रोल में बीस फीसदी इथेनॉल मिलाया जा रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की बचत व आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में प्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये ज्यादा इथेनॉल वाले ई-85 फ्यूल उपलब्ध कराया गया। लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच कई मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। दरअसल,ये वाहन ई-85 यानी 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल तथा ई-100 यानी शुद्ध इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिये डिजाइन किये गए हैं। जबकि पेट्रोल से चलने वाली सामान्य गाड़ियां ई-20 यानी बीस फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल के अनुकूल होती हैं। दरअसल, चुनिंदा आउटलेट्स पर ई-85 उपलब्ध कराने का निर्णय आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मकसद से लिया गया है। यह एक हकीकत है कि आज भी देश का नब्बे फीसदी कच्चा तेल आयातित किया जा रहा है। दुनियाभर में गाहे-बगाहे पैदा होने वाले भू-राजनीतिक संकटों ने बार-बार देश के ऊर्जा इकोसिस्टम की खामियों को ही उजागर किया है। इसमें दो राय नहीं है कि प्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये इथेनॉल को मुख्य ईंधन के रूप से बढ़ावा देने का मकसद ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर इसके उपयोग से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी ला सकते हैं। निश्चय ही वाहनों में इथेनॉल को बढ़ावा देना देश में आयातित कच्चे तेल के दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण

पहल है। लेकिन इस बदलाव को सिरे चढ़ाने के लिए बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों की आशंकाएं दूर हो सकें। जरूरत लोगों का भरोसा हासिल करने की है। भारत में इथेनॉल मिले तेल के उपयोग ने इससे होने वाले तमाम फायदों को साबित किया है। इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। साथ ही देश में इथेनॉल का सशक्त उद्योग विकसित हुआ है। यदि बाजार में इथेनॉल पर लोगों का भरोसा बढ़ता है और इसकी मांग बढ़ती है तो इससे किसानों को कमाई के नये अवसर मिल सकते हैं। इथेनॉल की ज्यादा मांग होने पर गन्ने और मक्का का बाजार विस्तार लेगा। वहीं दूसरी ओर ई-85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले कम रखने के फैसले से, उन उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है, जिनके पास इसके अनुकूल गाड़ियां हैं। भले ही इस फ्यूल की ईंधन दक्षता कम हो, लेकिन यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को संबल देगा। बहरहाल, इस उम्मीद के साथ ही, हमें हकीकत का भी ध्यान रखना है। दरअसल, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने इंजन की क्षमता, जंग लगने, ईंधन सिस्टम पर प्रभाव और इसकी दीर्घकालिक क्षमता को लेकर चिंताएं जतायी हैं। निस्संदेह, इन मुद्दों को सीधे खारिज करने के बजाय इन पर गंभीर रूप से मंथन करना चाहिए। अगर इन मुद्दों का निराकरण नहीं होता है तो भ्रम व संशय की स्थिति बनी रहेगी। जिसे अविलंब दूर करने की भी जरूरत है। इस वैकल्पिक ईंधन की सहज उपलब्धता के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व गाड़ियों को इसके अनुरूप बनाना, वैकल्पिक ईंधन की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण तथा इससे जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बाॅयोफ्यूल इतनी जल्दी फॉसिल फ्यूल का विकल्प नहीं बन सकता। इस बाबत पर्याप्त तैयारी, पारदर्शिता और सभी हितधारकों का सहयोग लेना जरूरी है। इस मामले में जल्दबाजी करने से बचा जाना चाहिए। यदि हम सजगता व सतर्कता से आगे बढ़ते हैं तो ई-85 एक सफल मॉडल बन सकता है। अन्यथा हम एक अच्छा मौका चूक सकते हैं।

बेहतर प्रबंधन से दूर हो सकेगा जल संकट

लेकिन केवल समुद्री जल शोधन से भारत की सभी जल समस्याओं का समाधान संभव नहीं होगा। वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, तालाबों और झीलों का संरक्षण, नदियों की स्वच्छता तथा उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को समान प्राथमिकता देनी होगी। दरअसल, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पानी की कमी नहीं, बल्कि जल प्रबंधन की है। हर वर्ष अरबों घन मीटर वर्षा जल बिना उपयोग के समुद्र में चला ...

यदि भारत में उपलब्ध जल का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए और समुद्री जल शोधन जैसी आधुनिक तकनीकों को साथ जोड़ा जाए, तो आने वाले दशकों में जल संकट की गंभीरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। देश के अनेक शहरों और गांवों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वर्षा का स्वरूप अनिश्चित होता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। तीन ओर से समुद्र से घिरे भारत के सामने जल का असीमित भंडार मौजूद है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97 प्रतिशत भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में है, जबकि केवल लगभग 2.5 प्रतिशत जल मीठा है। इसमें भी अधिकांश जल हिमनदों और बर्फ की चादरों में बंद है तथा मानव उपयोग के लिए सीधे उपलब्ध मीठा जल एक प्रतिशत से भी कम है। ऐसे में समुद्री जल को शुद्ध कर उपयोग योग्य बनाना भविष्य की आवश्यकता बनता जा रहा है।

आज आधुनिक विज्ञान की सहायता से समुद्री जल से नमक और अन्य अशुद्धियां हटाकर उसे पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे समुद्री जल शोधन कहा जाता है। विश्व के अनेक देशों ने इसे अपनी जल सुरक्षा की आधारशिला बना लिया है।

भारत के लिए भी अब इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ने का समय आ गया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत,



बहरीन और ओमान जैसे देशों में प्राकृतिक मीठे जल के स्रोत अत्यंत सीमित हैं। वहां वर्षा नगण्य होती है और अधिकांश भूभाग रेगिस्तान है। इसके बावजूद वहां नागरिकों को चौबीसों घंटे सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य कारण समुद्री जल शोधन संयंत्र हैं। भारत की स्थिति खाड़ी देशों से अलग अवश्य है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जबकि मीठे जल संसाधनों में उसकी हिस्सेदारी केवल लगभग 4 प्रतिशत है। देश में उपलब्ध मीठे जल का लगभग 80 प्रतिशत उपयोग कृषि क्षेत्र करता है। दूसरी ओर, उद्योगों और शहरों की बढ़ती

आवश्यकताओं ने जल संकट को और गहरा कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता भूजल का लगातार दोहन है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान,

दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों में भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। कई क्षेत्रों में हर वर्ष लगभग एक मीटर तक जल स्तर गिरने की रिपोर्ट सामने आती रही है। ऐसे समय में समुद्री जल शोधन भारत के लिए एक रणनीतिक विकल्प बन सकता है। देश के पास लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर समुद्री जल शोधन

परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं। इससे तटीय शहरों की पेयजल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा किया जा सकता है और भूजल पर निर्भरता कम होगी। चेन्नई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आज यह अपने पेयजल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री जल शोधन संयंत्रों से प्राप्त करता है। गुजरात के दहेज, जामनगर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इस तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, यह भी सत्य है कि समुद्री जल शोधन कोई जादुई समाधान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती लागत है। संयंत्रों की स्थापना, संचालन और रखरखाव पर भारी निवेश की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, बड़ी मात्रा में ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है। यदि ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन हो, तो लागत बढ़ने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता है। आज भारत विश्व के अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विशाल सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है। यदि समुद्री जल शोधन संयंत्रों को नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ा जाए, तो उनकी परिचालन लागत और कार्बन उत्सर्जन दोनों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। एक अन्य चुनौती पर्यावरण संरक्षण की है। समुद्री जल से नमक अलग करने के बाद अत्यधि क खारा अवशेष बचता है। यदि इसे वैज्ञानिक उपचार के बिना समुद्र में छोड़ दिया जाए, तो समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नई परियोजना के साथ कठोर पर्यावरणीय मानकों का पालन और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। भारत को इस क्षेत्र में चरणबद्ध रणनीति अपनानी चाहिए। पहले चरण में प्रमुख तटीय शहरों में बड़े समुद्री जल शोधन संयंत्र स्थापित किए जाएं। दूसरे चरण में तटीय औद्योगिक क्षेत्रों को समुद्री जल आधारित जलापूर्ति से जोड़ा जाए, ताकि उद्योगों द्वारा मीठे जल का उपयोग कम हो। तीसरे चरण में पाइपलाइन नेटवर्क विकसित कर निकटवर्ती आंतरिक क्षेत्रों तक भी शुद्ध जल पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा सकती है।

दुनिया की छत से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी

भारत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम (ईएमएएलएस) चीन से काफी पीछे है। चीन फुजियान (टाइप 003) विमान वाहक पर अपने विद्युत चुम्बकीय कैटापुल्ट को सफलतापूर्वक चालू कर चुका है, अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला वह दुनिया का दूसरा देश है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ग्राउंड फोर्स रिसर्च इंस्टिट्यूट में तैनात प्रोफेसर हान ने इसे दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट बताया, और कहा कि यह पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक बड़ी सफलताओं के साथ लगातार चल रहा है। हान ने '4,000 मीटर (13,123 फुट) से ज्यादा ऊंचे पठार से सीधे डेटा इकट्ठा किया है।

उन्होंने इस पर अनुसंधान किया है कि रॉकेट को ज्यादा ऊंचाई वाले माहौल के लिए कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, जहां सर्दियों में तापमान बहुत कम होता है, जिससे हवा का दबाव कम होता है। यह समुद्र तल के प्रेशर का लगभग आधा हो सकता है। इसका मतलब है उड़ान के दौरान हवा का घर्षण कम होता है, और शायद रेंज भी ज्यादा होती है, खासकर तिब्बत जैसे दुनिया की छत पर रॉकेट को और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बना देगा।' जियांग चीन के पूर्वी सिचुआन प्रांत का शहर है। 2026 की शुरुआत में जियांग में हाई-टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग नेविगेशन सिस्टम के सफल परीक्षण ने इस टेक्नोलॉजी को हकीकत के करीब ला दिया है। इस

प्रोजेक्ट का नेतृत्व 'जियांग कमर्शियल एयरोस्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टिट्यूट' के शोधार्थी कर रहे हैं, जो चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की एक शाखा है। तकनीकी सफलताओं के बावजूद, अभी भी इंजीनियरिंग से जुड़ी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। जियांग फैसिलिटी चीन के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म को सक्रिय रूप से चला रही है, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2028 तक 'इसरो' की तरह व्यावसायिक लांच वाले पैटर्न पर लाना है। अब सवाल है, क्या चीन इस तकनीक का सैन्य इस्तेमाल भी करने के प्रयास में है? चीन विद्युत-चुंबकीय तकनीक का इस्तेमाल मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में आक्रामक रूप से कर रहा है। पारंपरिक रासायनिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए, चीन इस तकनीक को जीरो-स्टेज ब्रूटर के रूप में विकसित कर रहा है। चीन की जियांग कमर्शियल एयरोस्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टिट्यूट एक

ऐसे सुपरकंडक्टिंग मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम पर काम कर रही है, जो रॉकेट को जमीन से ही ट्रैक पर बिजली के जरिए सुपरसोनिक गति देने में सक्षम है। इससे रॉकेट के इंजन हवा में बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही काम करेंगे, जिससे भारी लागत और ईंधन की बचत होगी। मिसाइल तकनीक के साथ चीन उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव (एचपीएम) और ईएमपी हथियारों का निर्माण कर रहा है। चीन ने अंतरिक्ष में मौजूद दुश्मन के सैटेलाइट्स या संचार प्रणालियों को बिना किसी विस्फोट के जाम या नष्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक का उपयोग कर रहा है।

सिद्धार्तनगर का सबसे बड़ा फ़िटींग पब्लिकेशन हाउस...
किट्टीभीस्वाडीडिजिटलीकडीआईडी

बुद्ध पब्लिकेशन
ऑफसेट एण्ड प्रिन्टर्स

जी.एस.टी. श्रित बुक/फ़ार्म **कायोल्ल रीक्रेटर** **स्वतुल कापी/फ़ार्म/अवरो** **फ़पलेट**
कलर पलेट **कलर डिप्लिटी कार्ड** **कलर लेट पेट** **बैक फ़ार्म**
लिकेट-टीरो एजेन्सी. बीजळ नद्यकरपूर-सिद्धार्थनगर (3.पू.)
९ 8795951917, 9453824459

Email: info@buddhakasandesh.com
 Website: www.budhakasandesh.com
 Address: B-1, Budhakasandesh, New Market, Gurgaon, Haryana

धान की रोपाई के दौरान दबंगों ने मारपीट कर घायल किया: कार्रवाई की मांग

सामाजिक कार्यकर्ता अभयदेव शुक्ल ने किया सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज की मां—बहनों को गाली देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

चलाया जा रहा है इसकी जांच कर बी०एन०एस० की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर समुचित कार्रवाई की जाय। उक्त फेसबुक यूजर द्वारा मैसेंजर और चैट के माध्यम से पीड़ित पक्ष (हर्षित दुबे) तथा बहनों और बेटियों के लिए अत्यंत अभद्र, अश्लील, और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। उसके द्वारा न केवल अत्यधिक अश्लील गालियों का प्रयोग किया गया है, बल्कि एक पोस्टर पर, अत्यंत आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्द लिखकर उसे प्रसारित किया गया है, जिससे महिलाओं की गरिमा को गंभीर ठेस पहुंची है। यह

अभिषेक शुक्ला ने जिला युवा अधिकारी बनकर बढ़ाया मान

दैनिक बुद्ध का संदेश

बस्ती। गौर विकास खण्ड क्षेत्र छितहा शुक्ल निवासी अभिषेक शुक्ला ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता हासिल किया है। शिवेश ईट उद्योग करनीपुर एवं शिवेश ट्रेडर्स मनौरी के संचालक श्याम सुंदर शुक्ल के बड़े पुत्र अभिषेक शुक्ला ने कठिन परिश्रम कर यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उनका चयन जिला युवा अधिकारी / सहायक

निदेशक खेल मंत्रालय के पद पर हुआ है। परीक्षा परिणाम 1 जुलाई 2026 को घोषित हुआ। परिणाम आने के बाद परिवार के लोगों में हर्ष का माहौल है। अभिषेक शुक्ला ने केन्द्रीय विद्यालय में हाई स्कूल और 2013 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। कंप्यूटर साइंस से बीटेक आईआईटी कल्याणी पश्चिम

पतकारों के हित में सूचना निदेशक की बड़ी पहल, आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ आसान

दैनिक बुद्ध का संदेश
गोन्डा। जनपद के पत्रकार बंधुओं की सुविधा एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। अपर जिला सूचना अधिकारी, गोन्डा ने बताया कि सूचना निदेशक विशाल सिंह के निर्देशानुसार अब पत्रकार बंधुओं के लिए आयुष्मान भारत कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन पत्रकार बंधुओं ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया है, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, वे पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति (स्टेटस) देख सकते हैं। यदि पोर्टल पर उनका नाम प्रदर्शित हो रहा है और किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, तो वे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, गोन्डा से संपर्क कर आवश्यक संशोधन करा सकते हैं। अपर जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि जिन पत्रकार बंधुओं ने अभी तक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन करने के बावजूद उनका कार्ड नहीं बन पाया है, उनकी सुविधा के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शीघ्र ही एक नया ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया जाएगा। पोर्टल प्रारंभ होने के बाद पत्रकार बंधु अपना आवेदन जिला सूचना कार्यालय, गोन्डा के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पोर्टल के संचालन की तिथि एवं अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही सभी पत्रकार बंधुओं को तत्काल अवगत कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र पत्रकार इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें।

मां बाराही देवी मंदिर एवं सुखुई नदी के पुनर्जवन की पहल, सुंदरीकरण और संरक्षण पर निर्देश

अधिकारियों को निर्देशित किया कि तालाब का समुचित सुंदरीकरण, साफ—सफाई एवं सौंदर्यीकरण कर उसे जनहित के अनुरूप और अधिक उपयोगी बनाया जाए, ताकि ग्रामीणों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने मां बाराही देवी मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। स्थानीय लोगों ने अवगत कराया कि मंदिर के समीप प्रवाहित सुखुई नदी वर्तमान में विलुप्त होने की स्थिति में है। इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी तरबगंज एवं खण्ड विकास अधिकारी बेलसर को नदी की

साफ—सफाई, अतिक्रमण हटाने, सुंदरीकरण एवं पुनर्जीवन के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी तरबगंज प्रदीप कुमार, जिला विकास अधिकारी आदित्य तिवारी, डीसी मनरेगा जनार्दन प्रसाद, खंड विकास अधिकारी बेलसर रवि कुमार, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) रवि मिश्रा, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव, संबंधित ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जन नायकन को सीबीएफसी से मिली मंजूरी! जल्द सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की आखिरी फिल्म

शनाया कपूर दक्षिण सिनेमा में जमाएंगी पैर? फिल्म जॉम्बी रेड्डी के सीक्वल से जुड़ने की चर्चा



मां इंटी बंगारम ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड, बनी हाईएस्ट ग्रासिंग फीमेल लीड तेलुगू फिल्म



सामंथा रुथ प्रभु ने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। उनकी हालिया रिलीज फिल्म मां इंटी बंगारम सिनेमाघरों में ऐसी आंधी लाई कि तेलुगू सिनेमा का 17 साल पुराना एक महा-रिकॉर्ड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इसने अनुष्का शेटी की साल 2009 की ब्लॉकबस्टर अरुंधति को पछाड़कर इतिहास रच दिया है। अब सामंथा की ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगू महिला प्रधान फिल्म बन गई है।

सामंथा की फिल्म मां इंटी बंगारम से पहले अनुष्का शेटी की 2009 में आई फिल्म अरुंधति को तेलुगू सिनेमा में महिला-प्रधान फिल्मों के लिए सबसे बड़ा पैमाना माना जाता था। उस दौर में, जहां सिर्फ अभिनेताओं का बोलबाला था, अनुष्का ने अपनी दमदार और अनोखी भूमिकाओं से इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई थी, लेकिन अब सामंथा की मां इंटी बंगारम ने अनुष्का के उस 17 साल पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया है।

सामंथा की ये फिल्म 19 जून को रिलीज हुई थी। इसने दुनियाभर में 83 करोड़ और भारत में 50 करोड़ की बंपर कमाई कर ली है। इसके साथ ही ये तेलुगू सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला-प्रधान फिल्म बन गई है। सामंथा के प्रोडक्शन हाउस त्रालाला मूविंग पिक्चर्स ने इस ऐतिहासिक सफलता की पुष्टि की है, जिसके बाद से प्रशंसक बेहद गर्व के साथ सामंथा को क्वीन और सुपरस्टार कहकर बधाई दे रहे हैं।

कोडी रामकृष्ण की फिल्म अरुंधति ने अनुष्का शेटी के दम पर दुनियाभर में 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर लंबे समय तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला-प्रधान तेलुगू फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। अब मां इंटी बंगारम ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि, महानती ने 75 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी, लेकिन उसमें कीर्ति सुरेश के साथ दुलकर सलमान, सामंथा और विजय देवरकोंडा समेत कई बड़े सितारे भी अहम भूमिकाओं में थे। सामंथा की मां इंटी बंगारम ने सिर्फ तेलुगू सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया है, वहीं कल्याणी प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म लोकारुहुर चौप्टर 1- चंद्रा ने न सिर्फ अपनी इंडस्ट्री, बल्कि पूरे साउथ इंडिया (तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ सबको मिलाकर) में सबसे ज्यादा 300 करोड़ की कमाई करने वाली महिला-प्रधान फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है यानी सामंथा की फिल्म तेलुगू में नंबर-1 है और लोका पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा में नंबर-1 है।

तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म रजन नायकनय की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले इसे 9 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, हालांकि इसकी रिलीज डेट सीबीएफसी सर्टिफिकेशन इश्यू की वजह से टलती रही थी। लेकिन अब फैंस के लिए गुड न्यूज है। दरअसल खबरें हैं कि ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। चलिए जानते हैं ये कब थिएटर में दस्तक देगी?

रिपोर्ट के मुताबिक, जना नायकन को ए सर्टिफिकेट मिल गया है, जिससे इसकी अब इसकी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले, फिल्म के सर्टिफिकेशन प्रोसेस में मुश्किलें आ गई थीं क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने मंजूरी देने के बजाय दोबारा जांच की मांग की थी। इसके बाद प्रोडक्शन हाउस ने सीबीएफसी के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बाद में केस वापस ले लिया और रिव्यू प्रोसेस का रास्ता चुना।

वहीं सेंसर से मंजूरी मिलने की खबर के बाद, इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि मेकर्स जल्द ही फिल्म की थिएटर रिलीज की अनाउंसमेंट कर सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक एच विनोथ के निर्देशन में बनी यह फिल्म जुलाई 2026 में रिलीज हो सकती है। खबरों के मुताबिक, जन नायकन के प्रोड्यूसर्स अभी 16 जुलाई को फिल्म रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि, अगर यह तारीख मुमकिन नहीं हुई, तो 23 जुलाई पर भी विचार किया जा रहा है। विजय की इस फिल्म के लिए 31 जुलाई की तारीख भी एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन इस पर अभी पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसी दिन उनके बेटे जेसन संजय की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म सिग्मा भी रिलीज हो रही है।

वहीं अगर जुलाई में रिलीज मुमकिन नहीं हुई, तो जना नायकन के मेकर्स 7 अगस्त का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ये स्लॉट खाली है। यानी इस दिन कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। हालांकि जन नायकन की रिलीज डेट के बारे में प्रोड्यूसर्स की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।

जन नायकन का बजट 350 करोड़ से 380 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। यानी थलपति विजय की ये काफी मोटी लागत में बनी है। वहीं ये तमिल की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक बताई जा रही है। गौरतलब है कि इस फिल्म से थलपति विजय की फीस ही 220 से 250 करोड़ के करीब बताई जा रही है।

जन नायकन विजय के करियर का एक अहम प्रोजेक्ट है और यह उनकी आखिरी फिल्म भी है, क्योंकि इसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में उतर गए। एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में हैं। वहीं सपोर्टिंग कलाकारों में बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, प्रियामणि, ममिता बैजू, नारायण और कई अन्य शामिल हैं। इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र ने दिया है।

वेलकम टू द जंगल के आगे हार मानने को तैयार नहीं कॉकटेल 2, 13वें दिन भी खूब छापे नोट

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 ने पहले हफ्ते में जमकर



कलेक्शन जानते हैं। क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद होमी अदजानिया निर्देशित रोमांटिक एंटरटेनर फिल्म ने सिनेमाघरों में लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वीकडेज में इसकी कमाई थोड़ी सुस्त पड़ गई है। खासकर दूसरे बुधवार को यानी 13वें दिन इसके कलेक्शन सबसे ज्यादा मंदी देखी गई फिर भी इसने 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। फिल्म की कमाई की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक 13.50 करोड़ से खाता खोला था और पहले हफ्ते में 70.50 करोड़ कमाए। इसके बाद इसने 8वें दिन 4 करोड़, 9वें दिन 4.25 करोड़, 10वें दिन 4.40 करोड़, 11वें दिन 1.75 करोड़ और 12वें दिन 1.85 करोड़ कमाए थे। वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को कॉकटेल 2 ने 1.40 करोड़ कमाए हैं। इसी के साथ इस फिल्म की 13 दिनों की कुल कमाई अब 88.15 करोड़ रुपये हो गई है। कॉकटेल 2 ने आधिकारिक तौर पर कृति और शाहिद की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के 87 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया है। इसी के साथ ये फिल्म कृति के करियर की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म भी बन गई है।

कॉकटेल 2 ने रिलीज के 13 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 88.15 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है। अब ये 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। हालांकि इस मील के पथर को पार करने के लिए इसे 12 करोड़ के करीब और कमाना होगा। उम्मीद है कि इसकी कमाई में तीसरे वीकेंड पर तेजी आएगी और ये भी संभावना है कि ये 100 करोड़ बन जाए। देखने वाली बात होगी कि छटती कमाई के साथ क्या कॉकटेल 2 ने शतक जड़ पाती है या नहीं।

शनाया कपूर के लिए बॉलीवुड का सफर कुछ खास साबित नहीं हुआ। उनकी डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियां (2025) प्लॉप निकल गई। आदर्श गौरव के साथ सर्वोच्च फिल्म तू या



में भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। ताजा अपडेट है कि अभिनेत्री तीसरी फिल्म के लिए दक्षिण सिनेमा का रुख करने की तैयारी कर रही हैं। साल 2021 की जॉम्बी कॉमेडी फिल्म जॉम्बी रेड्डी के सीक्वल से अभिनेत्री तेलुगु फिल्म जगत में डेब्यू कर सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जॉम्बी रेड्डी के सीक्वल में शनाया के साथ तेजा सज्जा मुख्य किरदार में नजर आएंगे। तेजा को हनु-मान (2024) और मिराई (2025) जैसी फिल्मों ने जबरदस्त सफलता दिलाई है। बताया जा रहा है कि अभिनेत्री ने फिल्म की शूटिंग का एक छोटा शेड्यूल भी पूरा कर लिया है। हालांकि परियोजना से जुड़ी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है। यह अलग बात है कि शनाया के फैंस उनके साउथ में डेब्यू को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह पहली दफा नहीं है, जब शनाया का नाम साउथ की किसी फिल्म से जुड़ रहा हो। इससे पहले, उन्हें मोहनलाल की फिल्म वृषभा में शामिल करने का ऐलान किया गया था। नंद किशोर के निर्देशन में बन रही इस परियोजना को एकता कपूर के प्रोडक्शन का समर्थन मिला था। शनाया इस पैन-इंडिया फिल्म की शूटिंग के शुरुआती चरण में शामिल भी हुई थीं। लेकिन फिर खबरें आई कि तारीख संबंधी समस्याओं के कारण वह फिल्म से अलग हो गईं।

स्कैल्प सीरम का इस्तेमाल करने से मिल सकते हैं ये फायदे



स्कैल्प सीरम एक खास उत्पाद है, जो बालों की जड़ों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह सीरम बालों की जड़ों तक गहराई से पहुंचता है और उन्हें पोषण देता है। इसके नियमित उपयोग से बालों की गुणवत्ता में सुधार होता है और वे टूटने से बचते हैं। आइए जानते हैं कि स्कैल्प सीरम के इस्तेमाल से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

बालों की जड़ों को मिलता है पोषण
स्कैल्प सीरम में मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों तक पहुंचते हैं और उन्हें जरूरी विटामिन्स और खनिज प्रदान करते हैं। इससे बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और वे टूटने से बचते हैं। नियमित उपयोग से बालों की सेहत में सुधार होता है और वे स्वस्थ दिखते हैं। इसके अलावा सीरम बालों की जड़ों को नमी प्रदान करता है, जिससे वे चमकदार और मुलायम बनते हैं।

डैंड्रफ से मिलेगी छुटकारा
स्कैल्प सीरम डैंड्रफ की समस्या को भी दूर कर सकता है। इसमें मौजूद एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण डैंड्रफ के कारण होने वाले कीटाणुओं को खत्म करते हैं। इसके अलावा यह स्कैल्प की सफाई भी करता है और इसे स्वस्थ बनाए रखता है। नियमित उपयोग से स्कैल्प की नमी बनी रहती है और खुजली की समस्या भी कम होती है। इसके परिणामस्वरूप बालों की जड़ों में मजबूती आती है और वे टूटने से बचते हैं।

बालों का गिरना होगा कम
स्कैल्प सीरम बालों के गिरने की समस्या को कम करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और एमिनो एसिड बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे वे गिरते नहीं हैं। इसके अलावा यह रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व बेहतर तरीके से पहुंचते हैं। नियमित उपयोग से बालों की मात्रा में सुधार होता है और वे अधिक घने और मजबूत बनते हैं।

नए बालों की होगी वृद्धि
स्कैल्प सीरम नए बालों की वृद्धि को बढ़ावा देने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल और जड़ी-बूटियों के तत्व नए बालों की जड़ों तक पहुंचते हुए उन्हें पोषण देते हैं। इसके अलावा यह सीरम बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे नए बाल तेजी से बढ़ते हैं। नियमित उपयोग से बालों की सेहत में सुधार होता है और वे स्वस्थ दिखते हैं। इसके परिणामस्वरूप बालों की लंबाई और मोटाई में भी वृद्धि होती है।

रूखे और बेजान बालों में आएगी जान
स्कैल्प सीरम रूखे और बेजान बालों में जान डालने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद नमी देने वाले तत्व बालों को गहराई से नमी प्रदान करते हुए उन्हें मुलायम बनाते हैं। इसके अलावा यह सीरम बालों को चमकदार बनाता है, जिससे वे स्वस्थ दिखते हैं। इसके नियमित उपयोग से बालों की सेहत में सुधार होता है और वे टूटने से बचते हैं। इन सभी फायदों के लिए स्कैल्प सीरम को अपनी बालों की देखभाल रूटीन में जरूर शामिल करें।